सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 11 ● अंक: 344 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, बुधवार 21 जनवरी, 2026
मूल्य ₹ 3/-

हर एक कामयाबी और दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है।
-नेपोलियन हिल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20... 7 | राजभवनों व राज्य सरकारों में फिर... 3 | 2027 में सपा फिर करेगी जोरदार... 2

लोकतंत्र की परीक्षा चुनावों में नहीं, अदालतों की दहलीज पर!

एफआईआर का आदेश दिया और कुर्सी चली गयी

» संभल हिंसा केस में जज विभांशु सुधीर का तबादला

» जज के डिमोशन की खबर की गूंज सोशल मीडिया पर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनावों में नहीं, अदालतों की दहलीज पर होती है और जब किसी अदालत के आदेश के बाद अदालत में बैठने वाले जज की कुर्सी बदल दी जाए तब सवाल फैसले का नहीं परिस्थिति का हो जाता है।

उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में पुलिस अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने वाले तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला किये जाने की खबर है। खबर इसलिए और ज्यादा महत्तवपूर्ण हो जाती है कि उन्हें सीजेएम पद से हटाकर सिविल जज सीनियर डिविजन के रूप में पोस्टिंग दी गयी है। कानून के जानकार इसे डिमोशन के नजरिये से देख रहे हैं और सरकार का यह निर्णय सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहा है कि जज के साथ ऐसे इंसाफ की किसी को कल्पना भी नहीं थी। सवाल यही है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय है या उससे आगे कुछ।

विभांशू सुधीर ने दिये थे एफआईआर करने के निर्देश

संभल हिंसा मामले में उस समय एक अहम मोड़ आया था जब तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने सीओ अनुज चौधरी सहित मामले से जुड़े अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये थे। यह आदेश कानून की उस प्रक्रिया का हिस्सा था जिसमें अदालत प्रथम दृष्टया तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने का निर्देश देती है। इस आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर एक और घटनाक्रम सामने आया है। जज विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें सीजेएम पद से हटाकर सुल्तानपुर में सिविल जज (सीनियर डिविजन) के रूप में नियुक्त किया गया।

> यही वह क्षण है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था का तापमान मापा जाता है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कोई यह दावा नहीं कर रहा है कि तबादला दंड है पर पद परिवर्तन सजा है या किसी प्रकार का दबाव डाला गया।

न्यायपालिका स्वतंत्र हो और स्वतंत्र दिखाई भी दे

भारतीय संविधान न्यायपालिका को केवल स्वतंत्र नहीं करता बल्कि उसे स्वतंत्र दिखाई देने योग्य भी बनाता है। इसी कारण जजों की नियुक्ति स्थानांतरण और पदस्थापन को अत्यंत संवेदनशील विषय माना जाता है। इन प्रक्रियाओं से जुड़ी हर घटना केवल प्रशासनिक नहीं रहती बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी जुड़ जाती है। जब कोई जज पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है तो वह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। ऐसे में यदि उसी क्रम में उसका स्थानांतरण हो जाए तो यह न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर नहीं बल्कि न्यायपालिका की धारणा पर सवाल खड़े करता है।

प्रश्नों को जन्म देता है तबादला

न्यायिक सेवा में तबादले कोई असामान्य घटना नहीं हैं। पदों में परिवर्तन भी व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन कई बार समय और संदर्भ ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से प्रश्नों को जन्म देते हैं। संभल प्रकरण में भी चर्चा का केंद्र यही बिंदु है। यह खबर इसलिए असाधारण नहीं है कि एक जज का तबादला हुआ बल्कि इसलिए ध्यान खींचती है कि एक न्यायिक आदेश के बाद बदलाव सामने आया। यही वह क्षण है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था का तापमान मापा जाता है। यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि कोई यह दावा नहीं कर रहा है कि तबादला दंड है पर पद परिवर्तन सज़ा है या किसी प्रकार का दबाव डाला गया। लेकिन यह प्रश्न पूरी तरह वैध है कि क्या ऐसे संयोग न्यायपालिका के प्रति जनता के भरोसे को सहज बनाए रखते हैं।

नहीं आया कोई बयान सामने

इस पूरे घटनाक्रम में जज की ओर से कोई सार्वजनिक बयान कोई सफाई या कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसे न्यायिक मर्यादा की दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर जनता सवाल पूछ रही है और सवाल पूछना लोकतंत्र की अवमानना नहीं उसकी रक्षा का माध्यम है। न्यायपालिका प्रेस कांफ्रेंस नहीं करती। वह आदेशों प्रक्रियाओं और संस्थागत निर्णयों के माध्यम से संवाद करती है। इसी कारण तबादले का समय पद का स्वरूप और उसकी पृष्ठभूमि स्वाभाविक रूप से विश्लेषण का विषय बन जाते हैं। यह विश्लेषण न्यायालय के विरुद्ध नहीं बल्कि न्यायालय की गरिमा और विश्वसनीयता को बनाए रखने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

संभल हिंसा का मामला अपने आप में संवेदनशील

संभल हिंसा का मामला अपने आप में संवेदनशील है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे है और अदालत ने प्रक्रिया के तहत अपना आदेश दिया। यहीं से संस्थाओं के बीच संतुलन की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। यदि अदालत पुलिस को जांच के दायरे में लाने में असमर्थ हो तो कानून का अर्थ सीमित हो जाएगा। और यदि अदालत के आदेश के बाद अदालत ही असहज प्रतीत हो तो असहजता लोकतंत्र तक पहुंच जाती है।

कोर्ट के आदेश पर अमल का सवाल

संभल हिंसा मामले में अदालत के आदेश और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच टकराव की स्थिति भी सामने आई थी। तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीओ अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश पारित किया था उस आदेश पर पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्ण अमल न होने की बात भी सामने आयी थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जिले के तत्कालीन एसपी स्तर पर यह कहा गया कि जिन 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था उस निर्णय को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यह स्थिति इसलिए भी संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि यह सवाल खड़ा करती है कि जब अदालत किसी मामले में जांच का रास्ता खोलती है तो प्रशासनिक स्तर पर उस आदेश के अनुपालन की सीमा और प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। मामला कानून पुलिस और न्यायपालिका के बीच संतुलन को लेकर बहस का विषय बन गया है।

2027 में सपा फिर करेगी जोरदार वापसी : अखिलेश

» सपा प्रमुख बोले- 37 सांसद विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा ने 2027 यूपी विधान सभा चुनाव की तैयारियां अभी से आरंभ कर दी है। इसी क्रम सपा प्रमुख अपने सभी सांसदों के साथ बैठक कर उनको निर्देश देने लगे हैं कि आने वाले समय में कैसे चुनाव को जीतना है। बता दें लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई। अखिलेश अपने सांसदों से आगामी चुनावी रणनीति और संगठन मजबूत करने की चर्चा की। हर संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की स्थिति पर चर्चा हुई।

इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने सांसदों में कहा कि यह 37 सांसद 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे। इसीं क्र म में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और एसआईआर संबंधी कामों पर निगरानी के लिए पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के पुत्र पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को लगाकर भविष्य की अपनी रणनीति का संकेत दे दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं।

गिरावट के मामले में भाजपा और शेयर बाजार में मुकाबला

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल की नैतिक गिरावट व शेयर बाजार में गिरावट के बीच मुकाबला चल रहा है और दोनों में तेजी से गिरावट आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, भाजपा में नैतिकता की गिरावट व शेयर बाजार में गिरावट के बीच मुकाबला चल रहा है, दोनों ही बेतहाशा गिर रहे हैं। इन दोनों ही हालातों में नुकसान देशवासियों का ही है। उन्होंने कहा कि पहले जनता का अब निवेशकों का भरोसा भाजपा से उठ गया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को भारी गिरावट आने से निवेशकों के 9.86 लाख करोड़ रुपये डूब गए। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 1,065.71 अंक यानी 1.28 प्रतिशत फिसलकर 82,180.47 अंक पर बंद हुआ।

रायबेरली में लगे राहुल अखिलेश की जोड़ी के पोस्टर

भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पहने राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव के पोस्टर शहर में चस्पा किए गए। पोस्टर पर सपा लोहिया वाहिना के प्रदेश सचिव राहुल निर्मल बागी का भी चित्र लगा था और निवेदक के रूप में शिवम कुमार का नाम था। पोस्टर के नीचे पीडीए रक्षक लिखा था। इस पोस्टर ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस लोकसभा की तरह फिर से सीटों का बंटवारा कर सकते हैं।

हमारी पार्टी मजबूत है और एक है : जियाउर रहमान बर्क

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा, हमने अहम बैठक की है ताकि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ें और अपनी सरकार बनाए। हमारी पार्टी मजबूत है और एक है। जनता के भरोसे और उनकी मदद से सभी सांसद मिलकर प्रयास करेंगे कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए।

विनय व तेज नारायण मथेंगे लखनऊ कैंट विस क्षेत्र

अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी व पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय को लखनऊ महानगर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया है। इन्हें संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के साथ एसआईआर के तहत फार्म नंबर 6, 7 व 8 का काम पूर्ण कराने और आपत्तियों के निस्तारण के लिए प्रभारी भी बनाया गया है। लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। इस विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर वर्ष 2022 में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक चुनाव जीते थे। पाठक और विनय शंकर तिवारी कभी बसपा में साथ-साथ थे। सपा द्वारा विनय शंकर तिवारी को कैंट विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

भाजपा में खेला जा रहा है बिग बॉस का खेल : खेड़ा

कांग्रेस ने पीएम मोदी के बीजेपी अध्यक्ष नबीन को बॉस बताने पर साधा निशाना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कि नितिन नबीन अब पार्टी मामलों में उनके बॉस हैं को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तंज कसा है। पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा और आरएसएस आपस में खेल खेलते रह सकते हैं। कभी (आरएसएस प्रमुख) मोहन भगवत किसी के बॉस बनते हैं, कभी मोदी किसी के बॉस बनते हैं।

उन्होंने लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस का जिक्र करते हुए आगे कहा, क्या यहां बिग बॉस का खेल खेला जा रहा है? उन्होंने कहा, चुनाव कहां है? इसे चुनाव क्यों कहते हैं? पहले राष्ट्रपति की घोषणा करते हैं, फिर कहते हैं कि चुनाव होगा, और फिर कोई चुनाव होता ही नहीं। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं रही और चुनाव को ''प्रभावित करने का'' का मौका भी नहीं मिला। नितिन नबीन को मंगलवार को औपचारिक रूप से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। उन्होंने जेपी नड्डा का स्थान लिया है। खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, ''चुनाव कहां हुआ है, इसे चुनाव क्यों कहा जाए? आपने अध्यक्ष पहले घोषित कर दिया और फिर कहा कि चुनाव होगा, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। ज्ञानेश कुमार गुप्ता इसके विरोध में इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि उनकी कोई भूमिका नहीं है, वह कुछ प्रभावित नहीं कर सके, कुछ हेरफेर नहीं कर सके।'' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री एवं भाजपा के लोग 'बिग बॉस' का गेम खेल रहे हैं।

संतों के अपमान के लिए माफी मांगे भाजपा सरकार : गहलोत

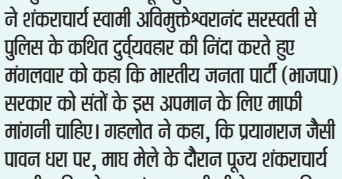

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से पुलिस के कथित दुर्व्यवहार की निंदा करते हुए मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को संतों के इस अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। गहलोत ने कहा, कि प्रयागराज जैसी पावन धरा पर, माघ मेले के दौरान पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार और उनका अन्न-जल त्यागकर धरने पर बैठना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने 'एक्स' पर लिखा, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार के राज में अगर सर्वोच्च संतों का यह हाल है, तो यह घोर पाप है। सत्ता के अहंकार में प्रशासन द्वारा माफी मांगने के बजाय संत को ही नोटिस थमाना 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि' का प्रमाण है। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार को संतों के इस अपमान के लिए तत्काल माफी मांगनी चाहिए।

कम से कम 100 दिन चले संसद व विधानमंडलों की कार्यवाही : मायावती

» मदरसे के बारे में हाईकोर्ट के आदेश का किया समर्थन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि संसद व राज्यों के विधानमंडल के सत्र कम से कम 100 दिन चलने चाहिए। सत्र के घटते समय के साथ हर बार हंगामेदार होने तथा स्थगन आदि से इनकी जन उपयोगिता घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है।

बसपा सुप्रीमो ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा कि लखनऊ में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के तीन-दिवसीय सम्मेलन के दौरान विधानमंडलों की कार्यवाही के लगातार घटते समय पर चिंता व्यक्त करना उचित, सामयिक व सराहनीय है। सरकार और विपक्ष को गंभीर होकर इस पर अमल करना चाहिए। संसद व राज्यों के विधानमंडल संवैधानिक व लोकतांत्रिक व्यवस्था के अहम स्तंभ हैं। सरकार एवं कार्यपालिका को देश व जनहित के प्रति उत्तरदायित्व बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम हैं। इनकी कार्यवाही वर्ष में कम-से-कम 100 दिन के कैलेंडर तथा सही नियमों के हिसाब से शांति-व्यवस्था के साथ चले, यह जरूरी है।

वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो ने श्रावस्ती में मदरसे को बंद करने के बाबत हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी मान्यता नहीं होना मदरसा को बंद करने का आधार नहीं संबंधी हाईकोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण व सामयिक है।

जम्मू का विभाजन हितकारी नहीं : उमर अब्दुल्ला

» सीएम बोले सीएम- एकता पर कोई समझौता नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के विभाजन की राजनीति करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के दो दिवसीय ब्लॉक अध्यक्ष सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने जम्मू-कश्मीर की एकता को अपरिवर्तनीय करार दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो लोग एक बार फिर राज्य को बांटने की मांग कर रहे हैं, वे न केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि जम्मू क्षेत्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) का ध्वज लहराता रहेगा, तब तक कोई भी ताकत क्षेत्रीय या धार्मिक आधार पर इस क्षेत्र को विभाजित करने का साहस नहीं करेगी। उमर यहां अपनी पार्टी के दो दिवसीय ब्लॉक अध्यक्ष सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सोमवार से शुरू हुए इस सम्मेलन की अध्यक्षता नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की। पिछले साल 16 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने 'दरबार मूव' को बहाल कर अपना चुनावी वादा पूरा किया। यह एक ऐसी प्रथा है, जिसके तहत सरकार छह-छह महीने जम्मू और श्रीनगर में काम करती है। लगभग 150 साल पहले डोगरा शासकों द्वारा शुरू की गई 'दरबार मूव' प्रथा को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जून 2021 में बंद कर दिया था।

'दरबार मूव' प्रथा को उपराज्यपाल ने बंद कर दिया

उमर अब्दुल्ला ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि 'दरबार मूव' को रोकने वाले या मेडिकल कॉलेज बंद होने का जश्न मनाने वाले लोग जम्मू के शुभचिंतक होने का दावा नहीं कर सकते। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की संकीर्ण, विभाजनकारी राजनीति ने पहले भी जम्मू को नुकसान पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाती रहेगी, जिसे नेकां सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा लहराता रहेगा, कोई भी ताकत जम्मू-कश्मीर को विभाजित नहीं कर सकती।

राजभवनों व राज्य सरकारों में फिर दिखी तकरार

राष्ट्रगान पर तमिलनाडु विधानसभा में भारी ड्रामा

- बंगाल, केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक में रार
- राज्यपाल आर.एन. रवि का वॉकआउट
- विजयन व आर्लेकर में भी ठनी
- राष्ट्रगान को उचित सम्मान मिलना ही चाहिए : रवि

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। एकबार फिर कु छ राज्यों के राज्यपाल सुर्खियों में हैं। खास तौर गैरभाजपा शासित राज्यों के। इनमे सबसे पहले तमिलनाडु के गवर्नर एन रवि है। उन्होंने विस में बंदे मातरम को लेकर प्रतिकि सा दी है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीमएसी सरकार ने राज्यपाल बोस से किसी बात की जांच को लेकर आग्रह किया है।

उधर कर्नाटक में आईपीएस के निलंबन की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा है। तमिलनाडु की राजनीति में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब राज्यपाल आर.एन. रवि साल के पहले सत्र के उद्घाटन पर अपना पारंपरिक अभिभाषण बीच में ही छोड़कर सदन से बाहर निकल गए। राज्यपाल ने न केवल भाषण पड़ने से इनकार किया, बल्कि राज्य सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए। गवर्नर रवि ने राज्य विधानसभा में कहा, मेरा माइक बंद कर दिया गया था, मेरा अपमान किया गया और मुझे बोलने नहीं दिया गया।

बंगाल में आरोप प्रत्यारोप तेज

राजनीतिक माहौल पहले से ही चुनावी राज्य बंगाल में गर्म है, जहां एसआईआर अभ्यास के चलते टीएमसी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं। इस विवाद पर भाजपा बंगाल इकाई के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने ममता के बयान को बिना आधार बताते हुए कहा वे सोचती हैं कि बंगाल उनका व्यक्तिगत राज्य है। वहीं, वामपंथी नेता एमडी सलीम ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को रक्षा मंत्री से पत्र लिखकर मामले की सच्चाई सामने लानी चाहिए।

केरल विधानसभा में राज्यपाल व सीएम में मनमुटाव

केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने मंगलवार को कहा कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विधानसभा में नीतिगत अभिभाषण के कुछ हिस्से नहीं पढ़े। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह अभिभाषण राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी से तैयार किया गया था, लेकिन राज्यपाल ने इसे पूरा नहीं पढ़ा। विजयन ने बताया कि राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ने के बाद सदन छोड़ दिया और इसमें से कुछ अहम हिस्से छोड़ दिए गए। इनमें अनुच्छेद 12 की शुरुआत और अनुच्छेद 15 का अंत शामिल था। छोड़े गए अंशों में केंद्र सरकार की नीतियों के कारण केरल पर पड़े वित्तीय संकट और राजकोषीय संघवाद से जुड़े मुद्दों का उल्लेख था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक अन्य छोड़े गए हिस्से में यह बात शामिल थी कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयक लंबे समय से लंबित हैं और इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विजयन ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नीतिगत अभिभाषण को ही आधिकारिक दस्तावेज माना जाए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ए एन शमसीर ने कहा कि परंपरा के अनुसार मंत्रिमंडल से मंजूर अभिभाषण में किसी भी तरह का बदलाव मान्य नहीं होता और यही नियम इस बार भी लागू रहेगा।

गवर्नर रवि ने व्यक्त की निराशा

विधानसभा में अपने संक्षिप्त संबोधन के दौरान राज्यपाल रवि ने गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा मैं बहुत निराश हूँ। राष्ट्रगान को वह सम्मान नहीं दिया गया जिसका वह हकदार है। इसे उचित सम्मान मिलना ही चाहिए। दरअसल, राज्यपाल की मांग थी कि सत्र की शुरुआत में तमिल गान के तुरंत बाद राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। जब स्पीकर एम. अप्पावु ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया, तो राज्यपाल ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए सदन का परित्याग कर दिया। यह तीसरी बार है जब उन्होंने पिछले दो सालों से पारंपरिक भाषण न देने के बाद वॉकआउट किया है। लोक भवन ने बताया कि गवर्नर आरएन रवि अपने उद्घाटन भाषण देने से पहले असेंबली से बाहर क्यों चले गए।

मामले की जांच की जाएगी : राज्यपाल बोस

राज्यपाल बोस ने कहा पहले मैं खुद सत्यापन करूंगा कि क्या मुख्यमंत्री ने कोई संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है। यदि ऐसा है, तो मैं निश्चित रूप से हस्तक्षेप करूंगा। वहीं, फोर्ट विलियम के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि राज्यपाल से बैठक हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी।

ममता बनर्जी के फोर्ट विलियम अफसर बयान पर सेना ने राज्यपाल से की शिकायत

पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोर्ट विलियम के एक वरिष्ठ सेना अधिकारी पर आरोपों के बाद विवाद चरम पर पहुंच गया है। ममता ने हाल ही में कहा कि अधिकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के दौरान भाजपा के समर्थन में काम कर रहे हैं और फोर्ट विलियम का कमांड बेस राजनीतिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बयान के बाद भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस से हस्तक्षेप की अपील की। जानकारी के अनुसार, दो सेना जनरलों ने पिछले सप्ताह राज्यपाल से मुलाकात कर ममता के आरोपों के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लोक भवन के अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया।

राज्यपाल ने वॉकआउट करने से पहले सदन में तीखे प्रहार किए

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण तथ्यात्मक रूप से गलत है और वे ऐसी बातें नहीं पढ़ सकते जो सत्य नहीं हैं। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी बात रख रहे थे, तब उनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने इसे अपना और अपने पद का व्यक्तिगत अपमान करार दिया।

अधिकारी बोला- एक मॉर्फ्ड वीडियो है

हालांकि, राव ने इन आरोपों से इनकार किया है, वीडियो को मनगढ़ंत और झूठा बताते हुए कहा, यह एक मॉर्फ्ड वीडियो है। लोग मुझे निशाना बना रहे राव ने बताया मैं आठ साल पहले बेलगावी में था, यह बहुत पहले की बात है। हमने इस बारे में अपने वकील से बात की है, और हम कार्रवाई कर रहे हैं। यह हमारे लिए चौंकाने वाला है। यह मनगढ़ंत और झूठा है। वह वीडियो पूरी तरह से झूठा है। मुझे नहीं पता कि कुछ हुआ है या नहीं; बिना जांच के यह सामने नहीं आएगा। इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसी झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। राव ने विवाद के बीच मामले पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री से भी मुलाकात की। हालांकि, इससे उनका सस्पेंशन नहीं रुक सका।

कर्नाटक में मचा हड़कंप, आईपीएस अधिकारी सस्पेंड

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए डीजीपी रैंक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई है, जिसमें कथित तौर पर अधिकारी को अपने सरकारी कार्यालय के भीतर विभिन्न महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। यह फैसला डीजीपी रैंक के अधिकारी के सरकारी ऑफिस में कथित व्यवहार को लेकर बढ़ते विवाद और लोगों के गुस्से के बीच आया। यह विवाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऑफिस तक पहुंच गया, जिन्होंने सोमवार को संबंधित विभाग से जानकारी ली। एक दिन बाद, राज्य प्रशासन ने सीनियर पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने का फैसला किया। इस घटना ने राज्य के राजनीतिक गलियारों और पुलिस महकमे में तूफान खड़ा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जब स्वयं फुटेज देखी, तो वे बेहद गुस्से में थे। उन्होंने विभाग से जवाब तलब किया कि पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारी ऐसी गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद 24 घंटे के भीतर निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया। इस घटना से सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा, विपक्षी पार्टियां इस पर करीब से नज़र रख रही थीं कि कोई औपचारिक जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या नहीं।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

कब तक गड्ढों में दफन होती रहेगा युवा भविष्य

जिस नोएडा के दम यूपी की सरकार विकास का दम भरती है। वहां के लापरवाह प्रशासन की वजह से एक युवक की मौत गड्ढे में समाने से हो गई। सबसे बड़ी विडंबना ये रही की प्रशासन के लोग समय से पहुंचे पर कोहरे व ठंड की वजह से गड्ढे में नहीं उतरे। हालांकि एक युवक ने घुस कर उसको बचाने की कोशिश की पर वह सफल नहीं हो सका। घटना की जानकारी के सीएम योगी ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की। पर प्रश्न यह उठता है कि इससे क्या होगा। वह युवक तो वापस नहीं आएगा। असली खलनायक कोहरा नहीं है असली विलेन वह प्रशासन है जो ऐसी घटना न हो उसके लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनाता। बस कागजों में सब सिमटा रहता है बाद में फिर किसी हादसे का इंतजार करता रहता हैं। बता दें एक कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार कोहरे के कारण नोएडा में निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट की ओर चली गई जहां गड्ढे में 30 फीट पानी भरा था। आखिरी समय तक जिंदा रहने की जद्दोजहद के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका।

पापा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो- आखिरी समय की गुहार अब उसके विवश पिता के कानों में जीवन के अंतिम समय तक गूंजती रहेगी, जिसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। पिता ने रात 12:25 बजे 112 पर इसी उम्मीद में फोन किया कि अब तुरंत बचावकर्मी आकर बेटे को सुरक्षित निकाल लेंगे पर, कंट्रोल रूम का रिस्पॉन्स इतना सुस्त था कि बचाव दल 50 मिनट बाद पहुंचा और सुबह चार बजे युवराज की लाश के साथ गड्ढे से बाहर आया। लापरवाही का कोई एक स्तर हो तो उसकी वजह समझने के प्रयास किए जाएं, यहां तो पूरा सिस्टम ही अपनी लापरवाही और अक्षमता का विज्ञापन करता दिख रहा है। इस दर्दनाक हादसे के लिए प्रारंभिक तौर पर मॉल निर्माता कंपनी के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा गड्ढ़ा बिना किसी घेरे के छोड़ रखा था। नोएडा विकास प्राधिकरण ने घटना के बाद बैरिकेट जरूर लगवा दिए पर, इसके अधिकारी पहले कहां व्यस्त थे? और अंत में क्विक रिस्पॉन्स टीम का 50 मिनट बाद रिस्पॉन्स? वह भी आधी-अधूरी तैयारी के साथ! बचाव टीम को डूबते युवक की कार तक पहुंचने में दो घंटे से ज्यादा समय लगना भी चकित करता है। कोहरे और ठंड के कारण शुरुआत में बचावकर्मी पानी में उतरने से कतराते रहे। युवराज कार की छत से मोबाइल की रोशनी दिखाकर अपना लोकेशन बताता रहा। यदि रिस्पॉन्स टीम 10 मिनट पहले पहुंचती तो युवराज जिंदा होता। क्विक रिस्पॉन्स टीम का यह हाल तब है जब कोहरे के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं । अब सचेत होना होगा।

"असली खलनायक कोहरा नहीं है असली विलेन वह प्रशासन है जो ऐसी घटना न हो उसके लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनाता। बस कागजों में सब सिमटा रहता है बाद में फिर किसी हादसे का इंतजार करता रहता है। बता दें एक कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार कोहरे के कारण नोएडा में निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट की ओर चली गई जहां गड्ढे में 30 फीट पानी भरा था।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

उथल-पुथल के बीच निर्णायक मोड़ पर ईरान

गद्दाम धर्मेंद्र

पिछले करीब तीन सप्ताह में हुए अभूतपूर्व देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों ने इस्लामिक गणराज्य ईरान को हिलाकर रख दिया है। ये जल्द ही रुक जाएंगे, ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं देता। ईरान में सामाजिक अशांति नई बात नहीं, लेकिन हाल में हुए सार्वजनिक प्रदर्शनों की तीव्रता से लगता है कि देश के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। इनको फरवरी, 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से, 47 सालों में सत्ता के समक्ष सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। देश में लॉकडाउन के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संचार और टेलीफोन सेवाएं बंद हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने वैश्विक सैटेलाइट संचार नेटवर्क 'स्टारलिंक' ब्लॉक करने को रूसी या चीनी मिलिट्री ग्रेड तकनीक का इस्तेमाल किया। अफवाहों और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी वाले माहौल में ईरान में मौजूदा स्थिति का सटीक अंदाजा मुश्किल है।

लेकिन, कई स्रोतों की रिपोर्ट है कि हाल के दिनों में सुरक्षा बलों ने बेरहमी से कार्रवाई की; जिसकी वजह से अब तक बड़ी संख्या में मौतें हो चुकी हैं और हज़ारों लोग हिरासत में लिये। आने वाले दिन या शायद हफ़्ते, तय करेंगे कि व्यापक तौर पर नापसंद मौजूदा सत्ता का भविष्य क्या होगा, हालांकि यह लंबे समय से कायम है और अगले महीने अपने 48वें साल में कदम रखने वाली है। 28 दिसंबर से शुरू होकर, संपूर्ण ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और दंगे हुए। आरंभ तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुआ। व्यापारी दुकानें बंद कर धरने पर बैठ गए, उनके विरोध की मुख्य वजह थी ईरानी मुद्रा, रियाल का अपने मुख्य मूल्य मापदंड अमेरिकी डॉलर के बरक्स बेतरह गिरना। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की सरकार द्वारा वित्तीय एवं आर्थिक सुधार करने के फैसले ने आग में घी डाल दिया, इसके पीछे हर चीज़ पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध भी एक वजह है। एक प्रस्ताव था कि तरजीही विनिमय दर व्यवस्था वापस ले ली जाए, जिसके तहत व्यापार संघ, जिन्हें वहां 'बाजारी' कहा जाता है, उन्हें भारी सब्सिडी पर बहुत कम दाम पर विदेशी मुद्रा मुहैया करवायी जाती है।

ये 'बाजारी' नियंत्रित विदेशी मुद्रा प्रणाली के तहत तरजीही सरकारी फंड की उपलब्धता का पूरा बचाव करते आये हैं। पेजेशकियन के फैसले ने सत्ताधारी मौलाना वर्ग को इस मुद्दे पर बांट दिया, जो अर्थव्यवस्था पर बाजारियों के प्रभाव से परिचित हैं। जो विरोध प्रदर्शन बाजारियों द्वारा दबाव बनाने की तरकीब के तौर पर शुरू हुए, वे जंगल में आग की तरह फैल गए, जिसमें छात्र और समाज का हरेक तबका शामिल हो गया, उनमें हताशा-निराशा लंबे समय से है, खासकर युवाओं में। इसके कुछ कारण हैं, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार की खस्ता हालत, उच्च महंगाई दर और सरकार का आर्थिक कुप्रंबधन, भ्रष्टाचार व सरकारी छूट का अनुचित लाभ लेने से लोगों में उपजी निराशा। ईरान में पिछले विरोध प्रदर्शनों का पैटर्न, जिसमें सबसे ताजा 2022 का हिजाब-विरोधी प्रदर्शन था, कुछ ऐसा रहा कि लोगों की नाराज़गी शुरू में तो किसी सामाजिक (हिजाब-विरोध) या आर्थिक शिकायत से भड़की, लेकिन तुरंत ही सियासी बगावत में बदल गयी। मौजूदा आंदोलन भी उसी पैटर्न पर है। हालांकि, इस बार, विरोध, और विरोध करने वालों की विविधता -जिसमें सभी वर्ग शामिल हैं- भरा विरोध जिस तेजी से फैला वैसी पहले कभी नहीं देखी। एक अतिरिक्त अवयव यह कि फलस्तीन, सीरिया व लेबनान के मामले में ईरानी सरकार के दखल से पड़े आर्थिक बोझ पर नाराजगी खुलकर जाहिर हुई है। सरकार के खिलाफ आम नारा 'तानाशाह को सजाए मौत' जिससे अभिप्राय सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई है- के अलावा अब 'न गाजा न लेबनान के लिए, मेरी जान है ईरान के लिए' जैसे नारे भी लग रहे हैं। एक नया अवयव है 'जाविद शाह' (शाह अमर रहे) का नारा है, यानी अमेरिका में निर्वासन काट रहे युवराज रेजा पहलवी। पहलवी इस बगावत का श्रेय चाहते हैं और खुद को बतौर सही विकल्प पेश कर रहे हैं। हालांकि ईरान की बिखरी राजनीति और पहलवी की ईरानियों की इस पीढ़ी से दूरी के चलते यह मुश्किल काम लगता है। राजशाही ईरानियों के बीच विवादास्पद मुद्दा है। उथल-पुथल की तीव्रता और उस पर सरकार की जानी-पहचानी सख़्ती ने पश्चिम एशिया के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में एक की अंदरूनी स्थिरता को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

जो हालात बन रहे, वे ईरान के पड़ोसियों के लिए भी गहरी चिंता की वजह होंगे। ईरान पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो भू-रणनीतिक एवं धार्मिक तौर पर अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी, सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। दोनों मुल्क सुन्नी और शिया पंथ की विचारधाराओं के जरिए इस्लामिक उम्माह की सरदारी के लिए होड़ में हैं। जबकि इस्लाम के ये दोनों पंथ भारत में शांति के साथ सह-अस्तित्व में हैं।

एक गौरवशाली विरासत से खिलवाड़ की कोशिश

डॉ. रामजीलाल

महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, दूरदृष्टा, राष्ट्रवादी नेता सरदार दयाल सिंह मजीठिया द्वारा शिक्षा प्रसार के लिए दिए योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र भुला नहीं सकता। उनके सपनों को साकार करने हेतु दिल्ली में स्थापित दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलने की अप्रिय कोशिश फिर हुई है। 'वीर बाल दिवस' के मौके पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर ने एक बार फिर दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हम कॉलेज का नाम बंदा सिंह बहादुर के नाम पर रखना चाहते हैं। दलील दी गई कि दयाल सिंह नाम के मॉर्निंग व इवनिंग कॉलेज होने से छात्रों को भ्रम होता है।

दयाल सिंह कॉलेज का एकेडमिक सेशन 1959 में शुरू हुआ और यह कन्फ्यूजन 67 साल बाद, 2026 में पैदा हुआ। कथित भ्रम के बावजूद शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेजों में 9300 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्वान और प्रतिभाशाली शिक्षकों के कारण कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के 10 शीर्ष कॉलेजों में आता है। सरदार दयाल सिंह मजीठिया (1848-1898), पंजाब के मजीठा गांव के एक महान सपूत थे, जो एक महान परोपकारी, राष्ट्रीय नायक और समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, उदारवाद और मानवता के प्रेमी थे। समाज में अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए, दयाल सिंह मजीठिया ने तीन ट्रस्टों की स्थापना की- द ट्रिब्यून ट्रस्ट, कॉलेज ट्रस्ट और लाइब्रेरी ट्रस्ट। उनके अथक प्रयासों के कारण, पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर की स्थापना 1882 में हुई। दयाल सिंह मजीठिया 'पंजाब नेशनल बैंक' (मई 1894) के संस्थापक भी थे। दयाल सिंह कॉलेज, लाहौर की स्थापना 1910 में दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट सोसायटी द्वारा, मजीठिया जी की वसीयत के अनुच्छेद 8 में दिए गए निर्देशों के अनुसार की गई थी। विभाजन के कारण दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट सोसायटी की अधिकांश संपत्ति लाहौर में ही रह गई। ट्रस्ट ने ईमानदारी से दयाल सिंह की विरासत और विचारधारा को आगे बढ़ाया। दयाल सिंह कॉलेज, करनाल (9 सितंबर, 1949), दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली (1954-55), और दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, दिल्ली (1958) की स्थापना की।

पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के संस्थापक वाइस-चांसलर दीवान आनंद कुमार ने इन एजुकेशनल संस्थानों को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली की स्थापना करने और फाइनेंशियल संकट से उबरने के लिए, ट्रस्ट को दयाल सिंह कॉलेज, करनाल की जमीन बेचनी पड़ी। 1978 में, फाइनेंशियल संकट के कारण, दयाल सिंह कॉलेज (मॉर्निंग और इवनिंग) को एक एग्रीमेंट के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर किया गया। ट्रस्ट सोसाइटी को बदले में कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन एग्रीमेंट के क्लॉज 12 के अनुसार, 'संस्थान को दयाल सिंह कॉलेज के नाम से ही जाना जाता रहेगा।' फलतः व्यक्ति या सरकार को एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है।

नवंबर 2017 में भी दयाल सिंह कॉलेज गवर्निंग बॉडी के तत्कालीन चेयरमैन अमिताभ सिन्हा इसका नाम बदलने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने कहा कि इवनिंग कॉलेज का नाम बदलकर 'पंडित मदन मोहन मालवीय कॉलेज' कर दिया जाएगा। 17 नवंबर, 2017 को, वे कॉलेज गवर्निंग बॉडी से दयाल सिंह कॉलेज का नाम बदलकर 'वंदे मातरम कॉलेज' करने और उसे मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट करने का प्रस्ताव पास करवाने में सफल रहे, जिसकी फाइनल मंजूरी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को देनी थी। इस कदम की सोशल मीडिया, अखबारों और टेलीविज़न चैनलों पर कड़ी आलोचना हुई। इसे शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता पर एक खतरनाक हमला भी माना गया। भाजपा की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल व कांग्रेस नेताओं ने भी इस फैसले की आलोचना की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के महासचिव मनजीत सिंह सिरसा और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह ने प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। एसजीपीसी के अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह मक्कड़ ने भी इसका विरोध किया। 27 नवंबर, 2017 को दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में आयोजित शिक्षाविदों और विद्वानों की बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलने से रोकने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाना था।

19 दिसंबर, 2017 को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान, कांग्रेस सांसदों आनंद शर्मा, अंबिका सोनी, ऑस्कर फर्नांडीस, एस.एस. ढींडसा और बी.के. हरिप्रसाद सहित कई सांसदों ने नरेश कुमार गुजराल के प्रस्ताव का समर्थन किया। तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सांसदों से कहा कि दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलने का फैसला केंद्र सरकार का फैसला नहीं था। उन्होंने गवर्निंग बॉडी के फैसले पर रोक लगाने की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन ने कुलपति के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के अनुसार 'यह कॉलेज प्रतिष्ठित सरदार दयाल सिंह मजीठिया की स्मृति से जुड़ा हुआ है। सभी शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और छात्र इस नाम से गहराई से जुड़े हैं। इतना महत्वपूर्ण फैसला हित धारकों से पूर्व परामर्श के बिना लिया गया।

शरीर की जरूरत के हिसाब से करें प्रयोग

दरअसल, कोई भी तेल सबसे अच्छा नहीं होता, यह आपके शरीर की जरूरत और मौसम पर निर्भर करता है। अगर आप हृदय रोगी हैं, या मालिश चाहते हैं तो सरसो के तेल का उपयोग करें। एनर्जी की जरूरत हो या कुछ फाइंग करना हो तो मूंगफली का तेल उपयोग में लाएं। ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में भी असरदार है। वहीं तीसरा तिल का तेल सर्दियों में जोड़ों के दर्द और ड्राय स्किन वालों के लिए असरदार है।

तिल का तेल

तिल का तेल आयुर्वेद में विंटर ऑइल कहा जाता है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है और स्किन की नमी बनाए रखता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन च पाया जाता है। तिल का तेल ठंड से शरीर को बचाता है, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में आराम देता है व हड्डियों को मजबूत बनाता है। वहीं स्किन को सर्दियों में सूखने से रोकता है। इसके अलावा एंटी-एजिंग प्रॉपर्टीज से शरीर को यंग बनाए रखता है। वहीं इसका स्वाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए खाना बनाते समय इसे दूसरे तेल के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है।

मूंगफली का तेल

मूंगफली का तेल, जिसे ग्राउंडनट ऑयल कहा जाता है, सर्दियों में शरीर को एनर्जी देने वाला तेल है। इसमें विटामिन ई, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स, और प्लांट प्रोटीन मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है। इसका स्मोक पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए डीप फाई के लिए बेहतरीन है। हालांकि, एलर्जी वाले लोगों को इसे सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। मूंगफली के तेल शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रैडिकल्स से बचाते हैं। यह खाना स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनाता है व उच्च स्मोक पॉइंट के कारण डीप फ्राई के लिए उपयुक्त होता है। वहीं जिन लोगों को मूंगफली से एलर्जी है, उन्हें इस तेल से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा, वजन घटाने वाले लोग इसे सीमित मात्रा में उपयोग करें।

सर्दियों में स्वास्थ्य के लिए ये तेल हैं फायदेमंद

पराठें पर घी, सब्जियों में तेल और शरीर पर सरसों की मालिश, ये सब सर्दियों में बहुत जरूरी है। सर्दियों में हमारे खाने-पीने की आदतों में भी बदलाव आ जाता है। ठंड के मौसम में शरीर को अतिरिक्त गर्मी और ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे में सही तेल का चुनाव करना बेहद जरूरी है। भारतीय रसोई में सबसे आम तीन तेल हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और तिल का तेल। लेकिन ठंड के मौसम में कौन सा तेल खाना सबसे सही है? सरसों, मूंगफली या तिल तीनों भारतीय रसोई के पुराने साथी हैं, पर इनका असर शरीर पर अलग-अलग होता है। अगर आप सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा की सेहत को को बेहतर रखना चाहते हैं, तो तिल का तेल सबसे अच्छा विकल्प है। वहीं, हृदय रोगियों के लिए सरसों का तेल ज्यादा फायदेमंद है। मूंगफली का तेल सामान्य कुकिंग के लिए अच्छा है। ऐसे में आप अपने शरीर और जरूरत के मुताबिक सर्दी में तेल का चयन करें।

सरसों का तेल

सरसों का तेल एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सरसो तेल में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हृदय को स्वस्थ रखते हैं। सर्दियों में यह शरीर को गर्म रखता है और त्वचा की नमी बनाए रखता है। यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। सरसों का तेल भारतीय घरों का परंपरागत तेल है। इसका उपयोग केवल खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर की मालिश और ठंड से बचाव के लिए भी किया जाता है। सरसो का तेल हृदय रोग से सुरक्षा देता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है व सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है और एंटी-बैक्टीरियल गुण संक्रमण से बचाते हैं। वहीं बालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। वहीं सरसों का तेल अगर ज्यादा तापमान पर बार-बार गर्म किया जाए तो ट्रांस फैट्स बन सकते हैं, इसलिए इसे ताज़ा और सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें।

हंसना मना है

एक लड़का घोड़े पर बैठकर कुछ लिख रहा था उसके पिता ने पूछा- तुम यहां क्यों बैठे हों? पुत्र- पिताजी! कल मास्टरजी ने घोड़े पर निबंध लिखने को कहा था, वही लिख रहा हूं।

प्रेमी- डियर! मैं तुम्हारे पिताजी से शादी की बात किस समय करूं? प्रेमिका ने कहा-जब कभी मेरे पिताजी के पैर में जूते न हों।

प्रेमी जोड़ा आपस में बातें कर रहा था। प्रेमिका- हम लोग दो साल से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्या तुमने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा? प्रेमी- दरअसल बात यह है कि मुझे गलत मत समझना, मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी तभी मैं तुम्हें कुछ जवाब दे सकूंगा..

पत्नी- शादी से पहले तुम मुझे होटल, सिनेमा, और न जाने कहां- कहां घुमाते थे, शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते.. पति- क्या तुमने कभी किसी को चुनाव के बाद प्रचार करते देखा है...

एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, ये स्कूल क्या होता है? पिता ने कहा, बेटा, स्कूल वह जगह है जहां तू अपनी गेंद और दिमाग दोनों खो सकता है!

कहानी | मूर्ख बकरी

एक जंगल में दो बकरियां रहती थीं। वो दोनों जंगल के अलग हिस्सों में घास खाती थीं। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी, जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था। इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इन दोनों बकरियों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन घास चरते-चरते दोनों बकरियां नदी तक आ पहुंची। ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थीं। अब एक ही समय पर दोनों बकरियां नदी के पुल पर थीं। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बकरी एक बार में गुजर सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस पर एक बकरी ने कहा कि सुनो, मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना।' वहीं, दूसरी बकरी ने जवाब दिया, 'नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना।' यह बोलते-बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच तक जा पहुंची। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थीं। अब बकरियों के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। पहली बकरी ने कहा कि पहले पुल पर मैं आई थी, इसलिए पहले मैं पुल को पार करूंगी।' तब दूसरी बकरी ने भी तुरंत जवाब दिया, 'नहीं, पहले मैं पुल पर आई थी, इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी।' यह झगड़ा बढ़ता चलता जा रहा था। इन दोनों बकरियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह कितने कम चौड़े पुल पर खड़ी हैं। दोनों बकरियां लड़ते-लड़ते अचानक से नदी में गिर गईं। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था, जिस कारण दोनों बकरियां उस नदी में बहकर मर गईं।

कहानी से सीख- झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है। इसलिए, ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए।

7 अंतर खोजें

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी। यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे। परीक्षा आदि में सफलता मिलेगी। पारिवारिक कष्ट एवं समस्याओं का अंत संभव है।

वृषभ

शत्रु सक्रिय रहेंगे। कुसंगति से हानि होगी। व्ययवृद्धि होगी। लेन-देन में सावधानी रखें, जोखिम न लें। किसी शुभचिंतक से मेल-मुलाकात का हर्ष होगा।

मिथुन
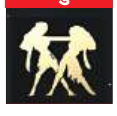
यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे। डूबी हुई रकम प्राप्त होगी। आय में वृद्धि होगी। प्रमाद न करें। आकस्मिक लाभ व निकटजनों की प्रगति से मन में प्रसन्नाता रहेगी।

कर्क

कार्यस्थल पर परिवर्तन लाभ में वृद्धि करेगा। योजना फलीभूत होगी। नए अनुबंध होंगे। कष्ट होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने से व्यस्तता बढ़ेगी। कार्य में नवीनता के भी योग हैं।

सिंह

कानूनी अड़चन दूर होगी। अध्यात्म में रुचि रहेगी। यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे। रुके धन के लिए प्रयत्न जरूर करें। कार्य का विस्तार होगा।

कन्या

चोट, चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें, बाकी सामान्य रहेगा। प्रयास अधिक करने पर भी उचित सफलता मिलने में संदेह है।

तुला

जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। राजकीय बाधा दूर होगी। बेचैनी रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। अर्थ प्राप्ति के योग बनेंगे। विवादों से दूर रहना चाहिए।

वृश्चिक

बेरोजगारी दूर होगी। विवाद न करें। संपत्ति की खरीद-फरोख्त हो सकती है। आय बढ़ेगी। मन में उत्साहपूर्ण विचारों के कारण समय सुखद व्यतीत होगा।

धनु
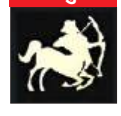
रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। प्रसन्नता बनी रहेगी। नए कार्यों से जुड़ने का योग बनेगा। पारिवारिक जीवन सुखद नहीं रहेगा।

मकर

बुरी खबर मिल सकती है। विवाद को बढ़ावा न दें। भागदौड़ रहेगी। आय में कमी होगी। किसी कार्य में प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से जुड़ने की प्रवृत्ति आपके लिए शुभ रहेगी।

कुम्भ

मेहनत का फल पूरा-पूरा मिलेगा। मान-सम्मान मिलेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। लाभ होगा। दूर रहने वाले व्यक्तियों से संपर्क के कारण लाभ हो सकता है।

मीन

मेहमानों का आवागमन होगा। व्यय होगा। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। अपने प्रयासों से उन्नति पथ प्रशस्त करेंगे। व्यर्थ समय नष्ट न करें। रुका पैसा मिलेगा।

बॉलीवुड | मन की बात

दूसरे को गिराने के लिए लोग खूब पैसा खर्च करते हैं : निधि अग्रवाल

निधि अग्रवाल हाल ही में प्रभास के साथ फिल्म 'द राजा साब' में नजर आई थीं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब निधि अग्रवाल ने पीआर कल्चर और पैसे देकर कराए जाने वाले निगेटिव पीआर पर अपनी राय रखी है। निधि ने बताया कि कैसे अक्सर पैसे का इस्तेमाल प्रतिभा को बढ़ावा देने के बजाय लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान निधि अग्रवाल ने खुलासा किया कि उन्हें भी निगेटिव पीआर का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इतना निगेटिव पीआर होता है। बहुत सारे तरीकों से हमले होते हैं। यहां तक कि बुक माय शो और आईएमडीबी रेटिंग्स जैसी चीजें भी। पेड रिव्यूज का एक खास वर्ग भी है। लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि लोग खुद को ऊपर उठाने से ज्यादा पैसा दूसरों को नीचे गिराने में लगाते हैं। हाल ही में मुझ पर भी एक दो निगेटिव अभियान शुरू हुए थे, लेकिन हमने उन्हें तुरंत रोक दिया। क्योंकि मैंने सोचा यार मैं तो खुद को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन अगर तुम कुछ नकारात्मक करोगे, तो मैं भी तुम्हें वैसा ही जवाब दूंगी। हाल ही में वरुण धवन और कार्तिक आर्यन पर हुए निगेटिव पीआर हमलों के बारे में बात करते हुए निधि ने कहा कि यह बहुत बुरा है। लोग इसके लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत ही खराब है। क्योंकि अभिनेता बहुत संवेदनशील और भावुक होते हैं। वे अंदर से बच्चों जैसे होते हैं। मुझे लगता है कि यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप पर हमला किया जा रहा है। सार्वजनिक हस्तियां सार्वजनिक संपत्ति नहीं होतीं। घर पर सबके माता-पिता होते हैं और आप उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। यह ठीक नहीं है। कार्तिक आर्यन और वरुण धवन की तारीफ करते हुए निधि ने उन्हें सच्चे इंसान बताया। उन्होंने कहा कि वरुण बहुत ही मासूम, प्यारे और प्रोत्साहित करने वाले हैं।

अभिनय के बाद अब सिंगर बनीं राशा थडानी अपनी ही फिल्म में देंगी सरप्राइज

फिल्म 'लईकी लईका' में राशा थडानी, मुंज्या फेम अभिनेता अभय वर्मा के साथ नजर आएंगी। मंगलवार को फिल्म से मेकर्स ने पहला गाना 'छाप तिलक' रिलीज किया। खुद राशा ने भी इस गाने के रिलीज होने की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस के साथ शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस गाने में क्या खास है ?

फिल्म के इस पहले गाने 'छाप तिलक' की खास बात यह है कि एक्ट्रेस राशा ने खुद गाया है। इस गाने के जरिए राशा ने बतौर सिंगर डेब्यू किया है। एक्ट्रेस ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया। फिल्म के इस पोस्टर में राशा हुडी पहने नजर आ रही हैं। पोस्टर पर एक तरफ पंजाब के शहर फरीदकोट का नाम लिखा हुआ है वहीं दूसरी तरफ राशा का नाम लिखा है। राशा ने अपने इस कदम से फैंस को बता दिया कि वो एक मल्टीटैलेंटेड एक्ट्रेस हैं।

तमन्ना ने किया खूब सपोर्ट

राशा की इस पोस्ट पर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने स्वीट रिएक्शन देते हुए लिखा- 'मैं इसका और इंतजार नहीं कर सकती।' इतना ही नहीं, तमन्ना ने राशा को सपोर्ट करते हुए एक इंस्टा स्टोरी भी साझा की। इसमें उन्होंने राशा के लिए लिखा- 'छुपी रुस्तम, क्या कमाल गाना गा रही हो..' फिल्म 'लईकी लईका' के पोस्टर हाल ही में रिलीज हुए हैं। इसे सौरभ गुप्ता ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म की कहानी प्यार, दर्द और भरोसे पर केंद्रित होगी। यह इसी साल मार्च-अप्रैल में रिलीज होगी।

सीरियल किलर के छक्के छुड़ाएंगी डीसीपी रीटा फरेरा

भूमि पेडनेकर की सीरीज दलदल का ट्रेलर जारी

बॉलीवुड | मसाला

क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। मुंबई शहर की पृष्ठभूमि पर बनी दलदल की कहानी डीसीपी रीटा फरेरा (भूमि) के इर्द-गिर्द घूमती है। वह एक खतरनाक जांच पर निकलती हैं, जहां उन्हें एक बेरहम सीरियल किलर को पकड़ना होता है।

ट्रेलर में डीसीपी रीटा फरेरा (भूमि) की खौफनाक दुनिया का सफर दिखाया गया है, जिसे भूमि सतिश पेडनेकर ने बेहद सशक्त अंदाज में निभाया है। ट्रेलर में क्रूर और सोचे-समझे किए गए हत्याकांड सामने आते हैं, जो एक कातिल की घिनौनी सोच को दिखाता हैं। जैसे-जैसे लाशों की संख्या बढ़ती जाती है, रीटा इस अंधेरी और डरावनी जांच में खुद को और गहराई तक फंसा हुआ पाती है।

विश धामिजा की बेस्टसेलिंग किताब भेंडी बाजार पर दलदल आधारित है। इस सीरीज को अमृत राज गुप्ता ने निर्देशित किया है। विक्रम मल्होत्रा और सुरेश त्रिवेणी ने इसका निर्माण किया है। इसे श्रीकांत अग्निस्वरन, रोहन डिसूजा और प्रिया सग्गी ने लिखा है। भूमि सतिश पेडनेकर के साथ इस सीरीज में समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी अहम भूमिकाओं में हैं। दलदल का प्रीमियर 30 जनवरी को प्राइम वीडियो पर किया जाएगा।

अजब-गजब | यहां पर मादा जानवर को भी निकाल देते हैं बाहर

दुनिया की वो जगह, जहां महिलाओं की एंट्री पर है बैन

दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां कुछ नियम इतने सख्त होते हैं कि वे हैरान कर देते हैं। ऐसी ही एक जगह है ग्रीस की माउंट ऐथोस, जिसे 'होली माउंटेन' या 'एगियोन ओरोस' भी कहा जाता है। यह एक प्रायद्वीप है जो एजियन सागर में फैला हुआ है और यहां 20 ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स मठ हैं, जहां करीब 2000 साधु रहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां 1000 साल से ज्यादा समय से महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। ना सिर्फ महिलाएं, बल्कि ज्यादातर मादा पशु भी यहां नहीं रखे जा सकते।

यह नियम 'अवाटॉन'कहलाता है, जिसका मतलब है 'प्रवेश निषिद्ध'। यह नियम 1046 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन मोनोमैकस के समय से आधिकारिक रूप से लागू है, लेकिन इससे पहले से ही मठों में यह परंपरा चली आ रही थी। वजह है साधुओं की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को बनाए रखना। मठों को पुरुषों का एक बड़ा मठ मानकर देखा जाता है, जहां कोई भी स्त्रीलिंग का प्राणी प्रवेश ना करे ताकि साधुओं का ध्यान भटके नहीं। ऑर्थोडॉक्स परंपरा के अनुसार, माउंट ऐथोस को 'वर्जिन मैरी का बाग' कहा जाता है। किंवदंती है कि वर्जिन मैरी और संत जॉन

द इवेंजेलिस्ट एक तूफान में यहां पहुंचे थे। मैरी को इस जगह की सुंदरता इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे खुद के लिए मांगा। इसलिए यहां सिर्फ वर्जिन मैरी ही महिला का प्रतिनिधित्व करती हैं, कोई दूसरी महिला नहीं। इस वजह से यहां महिलाओं के अलावा मादा पशुओं पर भी प्रतिबंध है। गाय, भेड़, बकरी, मुर्गियां जैसी घरेलू मादा जानवरों को यहां नहीं रखा जाता।

हालांकि, इस जगह पर एंट्री के लिए कुछ अपवाद भी हैं। बिल्लियों (फीमेल कैट्स) को यहां जाने की अनुमति है क्योंकि वे चूहों को पकड़ती हैं और मठों की साफ-सफाई में मदद करती हैं। जंगली जानवर जैसे हिरण या पक्षी स्वाभाविक रूप से आते-जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कुछ सोर्स में कहा गया है कि मुर्गियां भी कभी-कभी अंडों के लिए रखी जाती हैं, लेकिन सख्त नियम घरेलू मादा पशुओं पर लागू होता है। माउंट ऐथोस ग्रीस का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। यहां जाने के लिए पुरुषों को भी विशेष परमिट लेना पड़ता है, जो थेसालोनिकी में आवेदन करके मिलता है। महिलाओं के लिए यह परमिट कभी नहीं दिया जाता। ग्रीक कानून के अनुसार, महिलाओं का प्रवेश करने पर 12 महीने तक की जेल हो सकती है। 1953 में एक महिला ने पुरुष वेश में प्रवेश करने की कोशिश की थी, जिसके बाद यह कानून और सख्त हो गया।

ये है दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ी, जरा सी चूक और सीधे मौत

दुनियाभर में कई ऐसी खतरनाक जगहें हैं, जिनके बारे में जानकर कलेजा कांप उठता है। इनमें से कुछ जगहों का निर्माण इंसानों ने किया है, तो कई जगहें प्राकृतिक हैं। ऐसे में आज हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह सीढ़ी कहां है? अगर नहीं जानते तो बता दें कि यह सीढ़ी जापान के गिफू प्रान्त के गेरो शहर में मौजूद है। इसे आजकल 'सबसे डरावनी सीढ़ी' कहा जा रहा है। कंक्रीट की एक ऊंची दीवार पर बनी यह सीढ़ी किसी सामान्य रास्ते जैसी नहीं, बल्कि एक खड़ी दीवार पर लगी लोहे की सीढ़ी या कंक्रीट की ऊर्ध्वाधर सीढ़ी जैसी दिखाई देती है। ऐसे में इस सीढ़ी पर जरा सी चूक का मतलब है सीधे मौत। पहली नजर में ऐसा लगता है कि इस पर चढ़ना सर्कस के किसी कलाकार का ही काम हो सकता है, क्योंकि आम इंसानों के लिए यहां बैलेंस बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। यह सीढ़ी गेरो टाउन के कनायामाचो जिले में मेज नदी के किनारे बनी 10 मीटर ऊंची तटबंध की दीवार पर स्थित है। हाल ही में एक शौकिया फोटोग्राफर द्वारा इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद दुनियाभर से लोग इसे देखने पहुंचने लगे। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सीढ़ी इतनी सीधी खड़ी है कि यह लगभग 90 डिग्री का कोण बनाती प्रतीत होती है। इसके पायदान इतने संकरे हैं कि उन पर पैर रखना भी मुश्किल है और सुरक्षा के नाम पर केवल एक पुरानी और जंग लगी रेलिंग लगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीढ़ी का निर्माण 1960 के दशक की शुरुआत में हुआ था। उस समय स्थानीय अधिकारियों ने जिले को बाढ़ से बचाने के लिए एक कंक्रीट का तटबंध बनाने का फैसला किया था। हालांकि, तटबंध बनने के बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि उनके पास मछली पकड़ने के लिए मेज नदी के किनारे तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लोगों की इसी मांग को पूरा करने के लिए आनन-फानन में इस सीढ़ी का निर्माण किया गया था। इस सीढ़ी के इतना खतरनाक होने का मुख्य कारण इसका 'ट्रेड-टू-राइजर' अनुपात है। आमतौर पर सीढ़ियों में यह अनुपात 2:1 का होता है, लेकिन यहां इसे 1:1 रखा गया है। हालांकि, प्रशासन ने इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया, लेकिन माना जाता है कि कम जगह और कम लागत में काम निपटाने के लिए इस डिजाइन को अपनाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर जोश में टीएमसी

» सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों के कसे पेंच

» सीएम ने जिलाधिकारियों के साथ की बैठक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकता। सुप्रीम कोर्ट के फै सले के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी पूरे जोश में वह। अब पूरी ताकत से तैयारी में जुट गई ह। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को जिलाधिकारियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा और इस बात पर जोर दिया कि लोगों को 'तार्किक विसंगतियों' के नाम पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। वहीं सांसद अभिषेक बनर्जी भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में वह मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। इन सबके बीच टीएमसी ने भाजपा पर भी तीखे वार प्रारंभ कर दिए हैं।

राज्य के अधिकारी ने बताया कि बनर्जी दोपहर के समय राज्य सचिवालय नबन्ना में मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों के साथ हो रही बैठक में अप्रत्याशित रूप से शामिल हुईं। अधिकारी ने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर से संबंधित सभी सुनवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि तार्किक विसंगतियों के बहाने लोगों को असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर की सुनवाई के कारण लोगों को तार्किक विसंगतियों को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और इस मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वैध घोषित किए गए दस्तावेजों को सुनवाई के दौरान बिना किसी अपवाद के स्वीकार किया जाना चाहिए। जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि दस्तावेज जमा करने के बाद रसीद जारी करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि निर्धारित तिथियों पर सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ मतदाताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। इस घटनाक्र म के बाद तृणमूल कांग्रेस निर्वाचन आयोग तथा भाजपा दोनों पर और हमलावर हो गई है। सोमवार को उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने निर्वाचन आयोग और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ''उच्चतम न्यायालय ने उन्हें (भाजपा और निर्वाचन आयोग को) करारा जवाब दिया है। वे अदालत में हार गए, अब हम उन्हें चुनाव में हराएंगे।

एसआईआर की सुनवाई में मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं

भाजपा व चुनाव आयोग पर हमले किए तेज

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलेंगे अभिषेक बनर्जी

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल से मिलने के लिए समय मांगा है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तृणमूल कांग्रेस ने सीईओ को ईमेल भेजकर 27 जनवरी को बैठक का अनुरोध किया है, जिसमें बनर्जी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, अग्रवाल उसी दिन तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर सकते हैं। यह अनुरोध ऐसे समय में आया है जब एसआईआर कवायद के दूसरे चरण में विशेष रूप से मतदाता सूचियों में तार्किक विसंगतियों से जुड़े मुद्दों को लेकर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को दिए थे निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों में अगले तीन दिन के भीतर ''तार्किक विसंगतियों'' की सूची में शामिल लोगों के नाम प्रदर्शित करे और सूची के प्रकाशन के 10 दिन के भीतर उन्हें सुनवाई के लिए बुलाए।

भाजपा से मिलने का सवाल ही नहीं : ओवैसी

» एआईएमआईएम का महाराष्ट्र नगर निगमों में गठबंधन से इनकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन- एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि समुद्र के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। ओवैसी ने अकोट में हुई हालिया घटना का जिक्र किया, जिसमें एआईएमआईएम पार्षदों ने भाजपा के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि अकोट में एआईएमआईएम के पांच पार्षदों ने चुनाव जीता था और पार्टी ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी।

ओवैसी ने कहा कि शुरुआत में पार्षदों ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस समूह में वे शामिल हुए हैं वह भाजपा से जुड़ा हुआ है। ओवैसी ने बताया कि इसके बाद पार्टी ने उन्हें तुरंत नगर आयुक्त को पत्र लिखकर अपना समर्थन वापस लेने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि बाद में यह बात सामने आई कि भाजपा नेता के बेटे को सह-विकल्प के माध्यम से पार्टी में शामिल किया गया था, जिसके बाद इम्तियाज जलील ने पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि एआईएमआईएम प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों से गठबंधन करने वाले किसी भी सदस्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि यह पता चला कि जब भाजपा नेता के बेटे को सह-विकल्प के माध्यम से पार्टी में शामिल किया गया, तो इम्तियाज जलील ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। चाहे भाजपा हो, एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार, अगर वे उनके साथ जाते हैं, तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

हरकतों से बाज नहीं आ रहे एलएसए कर्मी

» कंपनी के कर्मचारी 4 पीएम के कैमरे में कूड़ा बेचते हुए कैद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। नगर निगम की ओर से कूड़ा उठान का ठेका पाने वाली एलएस कंपनी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। गोमती नगर में फन मॉल से पहले सर्विस लेन पर एलएसए कंपनी के कर्मचारियों का खुलेआम कूड़ा बेचने का मामला सामने आया है। पूरी घटना 4पीएम के कैमरे में कैद हुई है। कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि कूड़े से भरी गाड़ी को कर्मचारियों ने प्लास्टिक के थैलों में खाली कर आंबेडकर चौराहे के पास रहने वाले मुजीवर नाम के कर्मचारी ने असमियों के हाथ बेच दिया।

जबकि नियमों के अनुसार शहर से उठाया गया कूड़ा सीधे एमआरएफ सेंटर/डंपिंग पॉइंट पर ले जाकर गिराया जाना चाहिए, लेकिन एलएसए कंपनी के कर्मचारी बीच रास्ते में ही कूड़े का सौदा करते नजर आए। यह पहला मामला नहीं है जब एलएसए कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले भी डोर-टू-डोर कूड़ा उठान में लापरवाही, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट से मनमाना पैसा वसूलने और नियमों की अनदेखी जैसी कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। मामले पर एलएसए कंपनी के रीजनल हेड अभय रंजन ने सफाई देते हुए कहा कि अगर कोई भी कर्मचारी कूड़े को एमआरएफ सेंटर पर नहीं गिरा रहा है और उसे बेचने जैसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, सवाल यह भी उठता है कि जब लगातार शिकायतें और अब वीडियो सबूत सामने आ रहे हैं, तो आखिर निगरानी व्यवस्था कहां चूक रही है। नगर निगम द्वारा निजी कंपनियों को दिए गए ठेकों की मॉनिटरिंग पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

अमित शाह-बीएल संतोष ने करवाया राजस्थान में वोटर लिस्ट में हेरफेर: डोटासरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। कांग्रेस ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर राजस्थान में मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर हेरफेर करने का आरोप लगाया। पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पर इस कथित साजिश का नेतृत्व करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में यह मुद्दा उठाया।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। डोटासरा ने कहा कि 3 जनवरी तक एसआईआर प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन उसी दिन जयपुर में हुई एक बैठक के बाद मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने की कथित योजना लागू की गई।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच आज

» नागपुर की पिच पर टॉस रहेगा अहम, स्पिनर्स का दिख सकता है दबदबा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नागपुर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खत्म होने के बाद अब दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होगा, जिसका पहला मुकाबला नागपुर के स्टेडियम में खेला जाएगा। आगामी टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए तैयारियों के नजरिए से दोनों टीमों के लिए ये सीरीज काफी अहम है।सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम का अब तक साल 2024 से टी20 वर्ल्ड कप में काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें इस सीरीज में भी सभी को उसी प्रदर्शन के जारी रहने की उम्मीद है।

यहां की पिच को लेकर बात की जाए तो इसपर अब तक स्पिन गेंदबाजों का दबदबा अधिक देखने को मिला है। अब तक यहां पर कुल 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 9 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है तो वहीं 5 मैचों में टारगेट का पीछा करने वाली टीम जीतने में कामयाब रही है। यहां पर अब तक खेले गए सभी टी20 मुकाबलों में खेल आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों का प्रभाव भी बढ़ता जाता है, जिनके खिलाफ मैदान बढ़ा होने की वजह से लंबे शॉट भी खेलना बल्लेबाजों के लिए स्थिति को और मुश्किल बना देता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेना फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में इस स्टेडियम में अब तक एक टी20 मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें कीवी टीम ने साल 2016 के टी20 वर्ल्ड कप के मैच में टीम इंडिया को 47 रनों से मात दी थी। वहीं यहां की पिच पर पहली पारी के औसत स्कोर को लेकर बात की जाए तो वह 145 से 150 रनों के बीच का देखने को मिलता है।

नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे ईशान: सूर्यकुमार

नागपुर। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरेंगे। सूर्यकुमार ने यह भी पुष्टि कर दी है कि श्रेयस अय्यर की जगह ईशान किशन को चोटिल तिलक वर्मा की जगह प्लेइंग-11 में जगह दी जाएगी। सूर्यकुमार ने कहा, ईशान तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि वह हमारी टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा हैं और उन्हें टीम में पहले चुना गया तो उन्हें मौका देना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले डेढ़ साल से वह भारत के लिए खेले नहीं हैं लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर चौथे या पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी की बात होती तो अलग सवाल होता। तिलक भी नहीं है तो ईशान हमारे पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं।

देश के सैन्य स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं मोदी : जयराम रमेश

ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप की मध्यस्थता के दावे पार करने वाले हैं सेंचुरी

कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किया प्रहार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। विपक्ष ने भाजपा नीत एनडीए गठबंधन व पीएम परकरार वार किया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के इन तथ्यहीन दावों पर चुप रहकर देश के सैन्य स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वाकई अमेरिका ने भारत पर व्यापारिक दबाव बनाया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के श्रेय लेने पर भारत में सियासत एक बार फिर गरमा गई है।

कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अच्छे मित्र (डोनाल्ड ट्रंप) अब तक 70 बार यह दावा दोहरा चुके हैं कि उन्होंने ही पिछले साल दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष को समाप्त करवाया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स% पर पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कल से पहले यह गिनती 68 थी। मंगलवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप के बयान के बाद यह 70 हो गई है। प्रधानमंत्री के अच्छे मित्र, जिनसे कई बार जबरन गले मिला गया है, ने इतनी बार घोषणा की है कि वह 10 मई, 2025 को ऑपरेशन सिन्दूर के अचानक रुकने के लिए जिम्मेदार थे।

प्रधानमंत्री का अच्छे मित्र को जबरन गले लगाना नहीं आया पसंद

प्रधानमंत्री के अच्छे मित्र और जिनसे कई बार जबरन गले मिला गया है, ने इतनी बार (70)घोषणा की है कि वह 10 मई, 2025 को ऑपरेशन सिन्दूर के अचानक और अप्रत्याशित रूप से रोके जाने के लिए जिम्मेदार थे।'' अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में कहा, ''मैंने 10 महीनों में आठ युद्धों को समाप्त करवाया, ये कभी न ख़त्म होने वाले युद्ध थे। कंबोडिया और थाईलैंड वर्षों से लड़ रहे हैं, कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा।

प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने वाला शहरी नक्सल

कांग्रेस सांसद और संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए भाजपा मुख्यालय में अपने संबोधन के दौरान शहरी नक्सल शब्द के प्रयोग पर स्पष्टीकरण मांगा। एक पोस्ट में जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या उनके विरोधियों को शहरी नक्सल कहा जाएगा। कांग्रेस नेता ने 2020 में राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस जवाब का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मंत्रालय इस शब्द का प्रयोग नहीं करता है।

शहरी नक्सल पर स्पष्टीकरण दें पीएम

कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज शहरी नक्सल% कहे जाने वाले खतरे की बात की। 11 मार्च 2020 को गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय शहरी नक्सल शब्द का प्रयोग नहीं करता है। 29 अप्रैल 2024 को स्वयं प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की मांग करने वालों और आर्थिक असमानताओं पर चिंता व्यक्त करने वालों को शहरी नक्सल मानसिकता से ग्रस्त बताया। क्या प्रधानमंत्री इस पर स्पष्टीकरण देंगे या उनका मानना है कि उनके विरोधी शहरी नक्सल हैं? 2020 में गृह मंत्रालय ने कहा था, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शहरी नक्सली शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि, भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना में शहरी गतिविधियों सहित वामपंथी उग्रवाद के सभी रूपों का समाधान किया गया है।

धार भोजशाला में शांति व्यवस्था बनाए रखें : दिग्विजय सिंह

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल/धार। धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने है। वर्ष 2026 में बसंत पंचमी शुक्र वार यानि 23 जनवरी को पड़ रही है। यह संयोग पहले भी तीन बार 2006, 2013 और 2016 में बन चुका है और उन सभी मौकों पर क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात देखने को मिले थे। ऐसे में इस बार पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। इस वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार शुक्र वार को आ रहा है।

पूर्व सीएम ने की बसंत पंचमी पर नमाज का समय तय करने की मांग

पूर्व में भी आया है और केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार धार जिला प्रशासन ने उसे शांति से दोनों पक्षों से मिल कर मनाने की व्यवस्था की थी। मैं प्रशासन व सरकार से ये कहना चाहूँगा कि एएसआई द्वारा 2003, 2013 व 2016 में पहले ही अपने दिए गए आदेश में यह सपष्ट कर चुका है कि जब भी कभी बसंत पंचमी का त्योहार और शुक्रवार की नमाज़ साथ में होती है तो बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से लेकर 1 तक और उसके बाद 3ः30 बजे से सूर्यास्त तक की जाएगी और दोपहर 1 - 3 का समय शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छोड़ा जाएगा। इस स्थिति में सरकार व प्रशासन की ये ज़िम्मेदारी है,एएसआई द्वारा पारित किए गए आदेश की पूर्ण पालन किया जाए और धार में अमन शांति का पैग़ाम दिए जाने की पूरी कोशिश करते हुए सांप्रदायिक उन्माद व अफ़वाह फैलाने वालो पर सख्त कार्यवाही की जाए। मैं सभी हिन्दू मुसलमान भाइयों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की अपील करता हूँ। हमारा प्रदेश अमन का प्रतीक है और सरकार व प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस अमन को क़ानूनी रूप से स्थापित किया जाए।

अपर्णा यादव ने बंद किया कमेंट सेक्शन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर अपने सभी पोस्ट्स में कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। इससे पहले उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कमेंट सेक्शन पब्लिक था। माना जा रहा है कि अपर्णा की सोशल मीडिया टीम ने यह फैसला उनके पति प्रतीक यादव की तलाक़ वाली पोस्ट के बाद लिया है।

प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए पत्नी अपर्णा यादव को जल्द डाइवोर्स देने का ऐलान किया था। प्रतीक यादव ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे, उन्होंने अपर्णा यादव को स्वार्थी और बुरी आत्मा बताते हुए कहा कि उनकी वजह से पारिवारिक रिश्ते खराब हो गए थे। पोस्ट में अपनी पत्नी की तस्वीर शेयर करते हुए प्रतीक यादव ने लिखा था कि वह इस महिला से जल्द से जल्द डाइवोर्स लेने जा रहे हैं। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, मैं इस मतलबी औरत को जल्द से जल्द डाइवोर्स देने जा रहा हूं. उसने मेरे परिवार के रिश्ते खराब कर दिए. वह बस मशहूर और असरदार बनना चाहती है।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेजा कानूनी नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

प्रयागराज। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर मेला प्रशासन से जुड़ा 19 जनवरी नोटिस 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लिया गया, तो सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी नोटिस के मुताबिक, 19 जनवरी का नोटिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिष्ठा, सम्मान, गरिमा और उनके आर्थिक स्रोतों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि यह पत्र ऐसे विषय में दखल देता है, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसे अदालत की गरिमा को चुनौती देने वाला कदम बताया गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में पत्र वापस नहीं लिया गया, तो अवमानना न्यायालय अधिनियम 1971 और संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही शंकराचार्य परंपरा और स्वामी जी की छवि को ठेस पहुंचाने के आरोप में भी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।इस पूरे मामले में अन्य तीन शंकराचार्यों की ओर से उठाए गए पुराने विवाद का भी जिक्र है। उनका कहना था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक अभी पूरा नहीं हुआ था और इसे लेकर 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया गया था. इसमें मांग की गई थी कि अपीलों के निस्तारण तक किसी भी तरह का राज्याभिषेक या पदाभिषेक न कराया जाए।

हरियाणा दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

उत्तराखंड-हरियाणा के कांग्रेस जिलाध्यक्षों को देंगे सियासी गुर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कुरुक्षेत्र (हरियाणा)। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को हरियाणा पहुंच गए हैं। वे पंजाबी धर्मशाला में हरियाणा व उत्तराखंड के कांग्रेस जिलाध्यक्षों को सियासी पाठ पढ़ाएंगे। धर्मशाला में उत्तराखंड व हरियाणा जिलाध्यक्षों की 13 जनवरी से कार्यशाला जारी है, जिसमें अभी तक अनेक केंद्रीय नेता उन्हें गुर दे चुके हैं।

राहुल गांधी करीब पांच घंटे तक जिलाध्यक्षों के बीच रहेंगे। उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेंगे तो वहीं उनके परिवारजनों से भी खुलकर चर्चा करेंगे। इससे पहले अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर एक बार फिर से बुधवार को वीआईपी मूवमेंट दिखाई दी। बुधवार को संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने विमान से एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे। सुबह 10:20 बजे उनका विमान एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचा था। राहुल गांधी के स्वागत के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित प्रदेश के सभी कांग्रेस सांसद भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने पहुंचने पर एक-एक राजनेता से मुलाकात की। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व सांसद वरुण मुलाना से भी कुछ मिनट बात की। इसके बाद राहुल गांधी अंबाला से वाहन के जरिए कुरुक्षेत्र के लिए निकल गएराहुल गांधी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल के आसपास चारों ओर बेरिकेडिंग की गई है तो पुलिस जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। राहुल गांधी के साथ हरियाणा प्रदेशाध्यक्षा राव नरेंद्र सिंह, प्रदेश प्रभारी बी के हरिप्रसाद, उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला ही रहेंगे जबकि कुरुक्षेत्र जिला के विधायक अशोक अरोड़ा, रामकरण काला व मनदीप चट्ठा को भी कार्यक्रम स्थल पर एंट्री मिलने की उम्मीद है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। महाराष्ट्र कार्यालय :- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in | RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।